International Journal of Research
Available at https://edupediapublications.org/journals
p-ISSN: 2348-6848
e-ISSN: 2348-795X
Volume 01 Issue 11
December 2014

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध:आधुनिक सन्दर्भ में

डॉ लक्ष्मी नारायण

परिचय:- भारत और पाकिस्तान में संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनैतिक मुद्दों कि वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस रिश्ते का मूल वजह भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक कई उलझाए है और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक कार्रवाई कर चुके हैं। इन देशों में तनाव मौजूद है जबकि दोनों ही देश एक दूजे के इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं।भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर विभाजन के कारण 1947 में स्वतंत्र देश के रूप में मानचित्र पर आए। दोनों में समानता का बिन्दु यही है कि दोनों ने एक साथ आजादी प्राप्त की, लेकिन इसके बाद दोनों की आधारभूत असमानताएं उजागर होने लगीं। भारत ने जहां लोकतंत्र व पंथनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया वहीं पाकिस्तान ने धार्मिक राय का रास्ता अपनाया, जिसमें प्रजातंत्र की असफलता स्वत: निहित थी। भारत ने जहां गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, वहीं पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों के गुट के साथ सहानुभूति व सैनिक सहयोग की नीति अपनाई। परिणामत: पाकिस्तान में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप स्वाभाविक था। जन्म से ही पाकिस्तान भारत के साथ सैनिक समानता प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन परिस्थितियां इसके विपरीत रही हैं, अत: दोनों के मध्य तनावपूर्ण सम्बन्धों का जन्म स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उनकी यात्रा की प्रकृति में ही निहित था। पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व को सिध्द करने के लिए चार बार भारत के साथ युध्द थोपने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की पृष्ठभूमि भावनात्मक लगाव एवं अप्रत्यक्ष घटनाओं का इतिहास है। निकटतम पड़ोसी होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी भारत-विरोधी एवं विधटनकारी नीतियों के कारण भारत से लगातार दूर होता गया। वर्तमान में आतंकवाद एवं कश्मीर विवाद से दोनों देशों के संबंध कड़वाहट से भर गए। भारत ने पाकिस्तान के साथ शांति, मित्रता एवं सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए सदैव गंभीर प्रयास किये हैं। किंतु पाकिस्तान द्वारा सदैव नकारात्मक प्रत्युत्तर दिया गया। वाजपेयी द्वारा की गयी लाहौरबस यात्रा तथा लाहौर घोषणा का जवाब कारगिल घुसपैठ के रूप में दिया गया। कारगिल प्रकरण से भारत की एक जिम्मेदार राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय छवि को और अधिक मजबूती प्राप्त हुई। कारगिल संघर्ष के बाद भी पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी दुष्प्रचार करना तथा सीमापार आतंकवाद को समर्थन देना जारी है समझौता एक्सप्रेस, दिल्ली-लाहौर बस सेवा के जारी रहने, तीर्थ यात्रियों तथा सांस्कृतिक कर्मियों के आवागमन से जनता के स्तर पर परस्पर सम्पर्क कायम हुआ है। पाकिस्तान के प्रति अपनायी गयी नरम नीति से सैन्य मनोबल में कमी, आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहन तथा

भारतीय जन-सामान्य में निराशावाद जैसे नकारात्मक परिणाम भी सामने आये हैं, किंतु इस नरम प्रकार की कूटनति ने पाकिस्तान के वास्तविक मंसूबों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पूरी तरह उजागर कर दिया है। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नयी सरकारने भी पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर दिया। इसी संदर्भ में 24 सितम्बर, 2004 को न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के मध्य शिखर वार्ता हूई। 26 नवम्बर, 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमलों और इस हमले में पाकिस्तान के तत्वों की संलिप्तता के कारण द्वि पक्षीय वार्ता प्रक्रिया को रोक दिया गया। 26/11 के आतंकी हमले के पश्चात् भारत-पाक संबंध अपने निम्नतम स्तर पर पहूंच चुके हैं। इस संबंध में भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि हमले में साजिश रचने वाले आतंकी समूहों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे अन्यथा उससे कोई वार्ता नहीं की जाएगी।भारत विभाजन के सात दशक बाद भी इस विभाजन का उद्देश्य अधूरा है. माना गया था कि अपने लिये अलग राष्ट्र की इच्छा रखनेवाले मुसलमानों की मुराद पूरी हो जायेगी, तो आशंकाओं के धुंध छंट जाएंगे, दोनों देश शांति के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होंगे. दोनों देशों के पहले सत्ता-प्रमुखों- पंडित जवाहर लाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना- की घोषित आकांक्षाएं यही थीं, लेकिन भारत-पाक संबंधों का इतिहास गवाह है कि हुआ ठीक इसके विपरीत. आजादी के बाद से ही पाकिस्तान भारत से बैर रखने लगा और कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से युद्ध के मैदान में भारत को ललकार कर कई बार मात खायी. जब उसे आभास हो गया कि सीधे युद्ध में भारत को पराजित करना या कश्मीर पर कब्जा करना संभव नहीं है, तब आतंकवाद को पाल-पोस कर छद्म युद्ध की राह पर चल पड़ा. एक ओर पाकिस्तान का भारत से बैर आजादी के बाद से आज तक निरंतर जारी है. दूसरी ओर, भारत में सरकारों के बदलने के साथ-साथ नीतियों में उतार-चढ़ाव आता रहा. पाकिस्तान के साथ दोस्ती के मकसद से नये-नये प्रयोग हुए, उदारता दिखाते हुए कई एकतरफा समझौते किये गये. लेकिन, आज स्वतंत्र भारत की तीसरी पीढ़ी भी पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने की चुनौतियों से जूझ रही है. इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं कि दो राष्ट्र आम जनजीवन में गहन और विस्तृत समानताओं के बावजूद आपसी संघर्ष की स्थिति में ठहर से गये हों. ऐसे में मुम्बई हमले के बाद पसरे तनाव और गम के पल में पिछले सत्तर सालों के कूटनीतिक प्रयासों की विफलताओं पर भी गौर करना मौजूं होगा...**

हमारी कूटनीति को सफल नहीं होने देगा पाकिस्तान

भारत के ऐतबार से देखें तो पाकिस्तान का बनना ही एक कूटनीतिक गलती थी. इसीलिए भारत-पाक के आपसी मसलों को हल करने के लिए भारत जो भी कूटनीतिक रास्ता अपनाता रहा, वह सब

फेल होते चले गये. अब तो यह कहना उचित होगा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों की विडंबना यह है कि भारत की कोई भी अच्छी कूटनीति सफल नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान इसे होने नहीं देगा. दरअसल, पाकिस्तान के पास एक ठोस मुद्दा है- भारत के खिलाफ नफरत रखना और यह दिखाना कि एक दिन वह कश्मीर को भारत से छीन लेगा. इस मुद्दे पर ही पूरा पाकिस्तान एकजुट होता है. हमेशा से पाकिस्तान का यही लक्ष्य रहा है, जिसे वह अपनी कूटनीतिक चालों के जरिये साधने की कोशिश करता रहता है. पाकिस्तान पहले यह सोचता था कि वह युद्ध करके भारत से जीत जायेगा और इसलिए उसने 1965 और 1971 के युद्ध लड़े, लेकिन वह दोनों युद्ध हार गया और 1971 में तो बांग्लादेश के रूप में वह दो टुकड़े भी हो गया. यहां पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलग होना भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है.

हर प्रधानमंत्री की सोच के हिसाब से नीति मे कुछ बदलाव भी आते रहे

हर प्रधानमंत्री की विदेश नीति में अपनी कूटनीति होती है, लेकिन इसमें दो बातें हैं- निरंतरता और बदलाव. पाकिस्तान को लेकर जो विदेश नीति नेहरू के समय में थी, वही आज भी है, बस इसमें थोड़ा-थोड़ा बदलाव आता रहा. बदलाव समय के हिसाब से जरूरी था. पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की निरंतरता जारी तो रही, लेकिन हर प्रधानमंत्री की अपनी सोच के हिसाब से कुछ बदलाव भी आते रहे. जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर डिक्लरेशन किया और उसके बाद लगा कि भारत-पाक के मसले पर बहुत से मसले हल हो जायेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं. इसलिए इसे कूटनीतिक गलती कही गयी.

.

कहने का अर्थ है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने स्तर पर कूटनीतिक गलती नहीं करता, हां जब वह कूटनीति सफल नहीं होती, तब उसे कूटनीतिक गलती करार दे दिया जाता है. पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कूटनीति बार-बार विफल होने का बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान की सेना वहां की सरकार चलाती है और उसके साथ हैं मौलवी-मुल्ला. पाकिस्तान की नागरिक सरकार के हाथ में बहुत कुछ है नहीं. पाक जनता भले भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहे, लेकिन पाक सेना और उसकी शह वाले दहशतगर्द भारत-पाक रिश्तों के लिए हमेशा अड़चन बने रहेंगे.

राजनीतिक चूकों का खामियाजा

पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर करने और दक्षिण एशिया में स्थायी शांति बहाल करने की दिशा में विवादों का सिलसिला

साल 1947 ने जहां एक ओर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में आजादी के सुखद सवेरे का अहसास कराया था, वहीं बंटवारे का कभी न भरनेवाला जख्म भी दे दिया. बंटवारे के

कुछ ही महीनों बाद भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने-सामने आ गयी थीं, कारण था- कश्मीर को हथियाने का पाकिस्तान का धूर्त प्लान. कश्मीर को हासिल करने के मकसद से पाकिस्तान चार बार भारत के सामने दम भरता नजर आया, लेकिन हर बार मुंह की खाने के बाद भी अपनी छद्म हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. पिछले 70 वर्षों के कुछ बड़े विवादों पर एक नजर...

1947 : विभाजन और स्वतंत्रता

अंगरेजों ने हिंदू बहुल पंथनिरपेक्ष भारत और मुसलिम राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित कर दिया. इससे उपजे दंगे और विस्थापन से लाखों लोगों की हत्या हुई और लाखों बेघर हो गये. बंटवारे के कुछ दिनों बाद जम्मू-कश्मीर ने भारत का हिस्सा होना स्वीकार किया, लेकिन पाकिस्तान धर्म के नाम पर कश्मीर पर दावा करता रहा, जो दक्षिण एशिया में अशांति का बड़ा कारण बना.

1947-48 का पहला युद्ध

आजादी के चंद दिनों बाद ही कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा भेजे गये मुसलिम चरमपंथियों के हमले की वजह से अक्तूबर, 1947 में भारत को महाराजा के बचाव में आना पड़ा. महाराजा ने तय शर्तों के आधार पर भारत में शामिल होना स्वीकार किया. संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम रेखा (सीजफायर लाइन) तय कर दिये जाने के बाद 1 जनवरी, 1949 को युद्ध समाप्त हो गया. पाकिस्तान इसके कुछ महीनों बाद ही छद्म हमलों का सहारा लेना शुरू कर दिया.

1965 का युद्ध

अप्रैल, 1965 में गुजरात के कच्छ के रण के पास सीमा गश्ती दलों के बीच विवाद पैदा हो गया. अगस्त माह में स्थानीय कश्मीरियों के वेश में 26 हजार पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुस गये. दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया और भारतीय सेना लाहौर स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गयी. कई दिनों तक चले युद्ध के बाद 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की दखल के बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गयी.

1971 का युद्ध

पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर तीसरी बाद दोनों देश फिर युद्ध के मैदान में आमने-सामने थे. पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच उभरे मतभेद से गृहयुद्ध की स्थिति बन गयी थी. ढाका में पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के खिलाफ भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी. इस युद्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में नया राष्ट्र बना. 1972 में शिमला समझौता शांति बहाली के दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना गया.

1989 : कश्मीर में चरमपंथी उभार

कश्मीर घाटी में 1989 में कुछ इसलामिक चरमपंथी गुटों ने आजादी की मांग को लेकर और कुछ गुटों ने पाकिस्तान में शामिल होने को लेकर विद्रोह कर दिया. इन विद्रोही गुटों को उकसाने और हथियार मुहैया कराने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका थी.

À 1999 का कारगिल युद्ध

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर समझौता करके संबंधों को सुधारने की दिशा में ठोस प्रयास कर रहे थे, लेकिन कारगिल में छद्म पाकिस्तानों के हमलों के बाद परिस्थितियां एकदम उलट गयीं. परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहला युद्ध था. इसी साल के अंत में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ तख्तापलट कर सत्ता पर काबिज हो गये थे.

कुछ प्रमुख समझौते

जिन्ना- माउंटबेटन वार्ता (1947) : पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मुहम्मद अली जिन्ना और भारत के गवर्नर जनरल लुइस माउंटबेटन के बीच कश्मीर मसले पर नवंबर, 1947 में वार्ता.

कराची समझौता (1949) : दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच 27 जुलाई, 1949 को सीजफायर समझौता.

लियाकत-नेहरू समझौता (1950) : लियाकत-नेहरू पैक्ट या दिल्ली पैक्ट के तहत दोनों देशों के बीच शरणार्थी, संपत्ति, अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दों पर समझौता.

सिंधु जल-संधि (1960) : सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियों के जल बंटवारों को लेकर 19 सितंबर, 1960 को समझौता.

ताशकंद समझौता (1966) : 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच 10 जनवरी, 1966 को शांति समझौता.

शिमला समझौता (1972) : 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद विवादों खत्म करने के लिए शिमला में 2 जुलाई, 1972 को दोनों देश सहमत हो गये थे.

दिल्ली समझौता (1973) : 28 अगस्त, 1973 को हुआ यह तीन देशों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच समझौता था.

इसलामाबाद समझौता (1988) : नॉन-न्यूक्लियर एग्रीमेंट के नाम से भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच 21 दिसंबर, 1988 को समझौता हुआ था.

मौलाना आजाद को था पाक की हरकतों का पूर्वाभास

पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित कई देशों में भारत की नुमाइंदगी करनेवाले अनुभवी राजनयिक जेएन दीक्षित (1936-2005) ने अपनी किताब 'भारत-पाक संबंध : युद्ध और शांति में' में आजादी के बाद से कारगिल युद्ध तक के घटनाक्रमों और कूटनीतिक फैसलों का विश्लेषण किया है. उनकी किताब के कुछ अंश हम यहां साभार प्रस्तुत कर रहे हैं.

भविष्य का अनुमान लगानेवाले एकमात्र राजनेता थे 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद. उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान का निर्माण भारत के मुसलमानों को नुकसान पहुंचायेगा और सीमा के दोनों ओर उनकी इसलामी पहचान के बारे में संकट उत्पन्न करेगा. उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि जातीय-भाषायी और कट्टरवादी शक्तियां भारत और पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान को प्रभावित करेंगी. उनकी स्पष्ट धारणा थी कि भारत एवं पाकिस्तान एक दीर्घकालीन शत्रुतापूर्ण संबंधों के रास्ते पर चलेंगे.

.

परिणाम की उम्मीद नहीं, फिर भी आगरा में बात

आगरा शिखर वार्ता मध्य जुलाई 2001 में हुई और अनिर्णित रही. अनुमान यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध आगरा की विफलता के फलस्वरूप उत्पन्न विकट परिस्थितियों पर केंद्रित रहेंगे. आगरा वार्ता से पहले भी भारतीय राजनेताओं से बातचीत में मैंने यही महसूस किया. मुझे सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. मैं प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा दिये भोज के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल सत्तार और खुद मुशर्रफ से भी मिला. इन वरिष्ठ राजनेताओं की सार्वजनिक मुद्रा जो भी रही हो, वे आगरा में नाटकीय परिणामों की अपेक्षा नहीं कर रहे थे. उनका यह मानना था कि बातचीत को बरकरार रखना एक कठिन प्रक्रिया होगी, जिस पर दोनों देशों की सरकारों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए. ये पूर्वानुमान 11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमले के बाद नाटकीय तरीके से बदल गये. दो माह बाद भारतीय संसद पर हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया.

कांधार विमान कांड के बाद मनन नहीं

कांधार विमान अपहरण समाप्त होने के बाद जन-प्रतिक्रिया को देखते हुए भारत को इस बात पर मनन करना चाहिए था कि उसने विमान अपहरण के मामले पर कैसा रवैया अपनाया. लोगों के एक वर्ग और मीडिया ने इस बात पर बल दिया कि अपहरणकर्ताओं के आगे झुकने से भारत की छवि खराब हुई है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि कुछ संगठनों ने यहां तक कहा कि भारत ने कायरोंवाला तरीका अपनाया. कुछ अन्य का विचार था कि भारत ने नरम देश की अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को और मजबूत कर लिया है. तो क्या कांधार में विमान के उतरने के बाद कोई अन्य विकल्प भी आजमाया जा सकता था?

पोखरण से पाक को सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद मिली

सन् 1974 व 1975 में भारत-पाक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली दो घटनाएं हुई थीं- 18 मई, 1974 को पोखरण में भारत का सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण और 15 अगस्त, 1975 को मुजीब की हत्या. पोखरण परीक्षण ने भुट्टो को भारत के खिलाफ पाकिस्तानी जनमत तैयार करने का मुद्दा प्रदान किया. इसने भुट्टो को अमेरिका व चीन के सहयोग से पाकिस्तान की सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद की, क्योंकि ये देश भारत के परमाणु संपन्न होने की आशंकाओं के मद्देनजर पाकिस्तान की सहायता के लिए तैयार थे. उन्होंने संकल्प किया कि पाकिस्तानी एक परमाणु अस्त्र बनायेंगे, चाहे उन्हें घास खाकर क्यों न रहना पड़े.

उसके बाद हुए सैन्य विद्रोहों और प्रतिरोधी विद्रोहों का अंत स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल रहे समूचे बांग्लादेशी नेतृत्व के खात्मे के साथ हुआ और इसने पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ एक अंतर्संबंध स्थापित करने में मदद की. मुजीब की हत्या के छह वर्षों के अंदर बांग्लादेश की सत्ता पाकिस्तान के समर्थक और चरमवादी इसलामी प्रवृत्तियोंवाले लोगों के हाथ में
चली गयी.

शिमला समझौते के बाद विवाद और शत्रुता के नये दौर की नींव

सन् 1974 और 1977 के बीच की अवधि, जब भुट्टो के हाथ से सत्ता निकलने वाली थी, भारत-पाक संबंधों में एक संक्रमण की अवधि थी , जिससे शत्रुता और तनाव में बढ़ोत्तरी हुई. युद्धबंदियों को रिहा करवाने और भारत के कब्जे से अपनी भूमि छुड़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद भुट्टो शिमला समझौते में निहित कुछ प्रतिबद्धताओं से विचलित होने लगे थे. शिमला समझौते के केवल दो माह बाद 7 सितंबर, 1972 को बोलते हुए शिक्षा मंत्री पीरजादा ने कहा, 'राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शिमला समझौते के अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की वापसी के बारे में पाकिस्तान कटिबद्ध नहीं था.' संयुक्त राष्ट्र को अपने पर्यवेक्षक वापस बुलाने के लिए कहने का कोई इरादा सरकार का नहीं था. (द न्यू पाकिस्तान - लेखक - सतीश कुमार, 1978, पृष्ठ 243).

शुरुआती फैसले ही विवाद की जड़

नेहरू के आदर्शवाद ने हमें जख्म ही जख्म दिये. जब अक्तूबर 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया, उस वक्त ही सरदार पटेल ने सेना भेज कर मामला सुलझाने का सुझाव नेहरू को दिया था, लेकिन नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी. वह इस मसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र चले गये, जिसकी वजह से आज भी कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है.

1966 के ताशकंद समझौते पर राजनीति हावी

1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद जब 1966 के ताशकंद समझौते पर दस्तखत हुए, उसमें भी राजनीति राष्ट्रनीति पर हावी रही. समझौता करने की वजह से भारतीय सेना, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा

पर करके लाहौर तक पहुंच चुकी थी, उसे वापस उसी स्थान पर जाना पड़ा, जहां वह युद्ध के पहले खड़ी थी.

1971 में बड़प्पन में कर बैठे एक और भूल

1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया था, तब भारतीय सेनाएं लाहौर तक जा पहुंची थी. उस समय भी मौका था, जब हम 1947 और 1965 की भूल को सुधार सकते थे, लेकिन इंदिरा जी के 'बड़प्पन' के कारण हम यहां भी चूक गये और अपना कश्मीर लिये बिना ही 90,000 पाक युद्ध-बंधक सैनिकों को छोड़ दिया.

बहुचर्चित 'गुजराल डॉक्ट्रिन' के बाद कमजोर हुए गुप्त और सामरिक संसाधन

फिर बहुचर्चित 'गुजराल डॉक्ट्रिन' ने जिस प्रकार भारत के सभी गुप्त और सामरिक संसाधनों को कमजोर किया, जो आगे चल कर आत्मघाती ही साबित हुआ. उसका नतीजा यह मिला कि कई राज्यों में आतंकी हमले झेलने पड़े. पिछले 70 वर्षों में हर बार भारत की ओर से किये हर विश्वास बहाली के प्रयास का पाकिस्तान ने हिंसा के रूप से उत्तर दिया है. हर बार उसने छल से भारत की पीठ में छुरा घोंपा है.

निष्कर्ष:- अब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई भी राजनीति न हो, यह हमारे राजनीतिक कुलीन वर्ग को सुनिश्चित करना होगा. सबको मिलकर सरकार और सेना का मनोबल बढ़ाना होगा, जिससे आतंक के इस खूनी खेल को सदा के लिए विराम दिया जा सके. **ऐसा नहीं है कि दोनों देशों ने सम्बन्धों को सामान्य बनाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आधारभूत परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया स्थायी नहीं हो सकी। अभी पाकिस्तान में एक ऐसे प्रभावशाली वर्ग का अभाव है, जो दक्षिण एशिया में शांति व सहअस्तित्व के माध्यम से वहां लोकतंत्र व विकास की कल्पना कर सके। अत: पिछले 6 दशको से भारत-पाक सम्बन्धों का इतिहास सामान्यीकरण के अपवादों के साथ तनाव और संघर्ष का इतिहास है।**

सन्दर्भ

1. *Lumby, E.W.R. (1954), The Transfer of Power in India, 1945–1947, London: George Allen and Unwin*
2. *Metcalf, Barbara D.; Metcalf, Thomas R. (2006), A Concise History of India (2nd ed.), Cambridge University Press, ISBN 978-0521682251*
3. Budania, Rajpal, "India's Pakistan Policy: A Study in the Context of Security," *South Asian Studies*, Vol.30:2,1995.
4. Burke, S.M.,*Mainsprings of Indian and Pakistani Foreign Policies*, Minneapolis, University of Minnesota, 1974.

5. Brines Russel, *The Indo-Pakistan Conflict*, London, Pall Mall Press, 1968.
6. Barrett, Scott, "Conflict and Cooperation in Managing International WaterResources," Policy Research Working Paper 1303, The World Bank, May 1994.Brigadier Desmond E Hayde, "The Battle of Dograi and Batapore", Natraj Publishers,New Delhi, 2006Dr. WasimMallik,
7. NewDelhi,Gulhati, Niranjan D., The Indus Waters Treaty: An Exercise in International Mediation,Allied Publishers: Bombay, 1973.Haroon Ahmed, INDUS WATER TREATY BETWEEN INDIA & PAKISTAN, research paper Jha,
8. *An Army; Its role and Rule (A History of the Pakistan Army FromIndependence to Kargil 1947–1999)*
9. Munir Ahmed Khan, NUCLEARISATION OF SOUTH ASIA AND ITS REGIONAL ANDGLOBAL IMPLICATIONS REGIONAL STUDIES, Autumn 1998Rafique Ahmad,
10. (Prospects for a durable Peace),Starlite Press, 176 Anarkali, LahoreRathnam Indurthy, Professor of Government at McNeese State University,
11. , 196-61, Ministry of External Affairs, Government of IndiaRose Gottemoeller, Carnegie Endowment for International Peace ENHANCINGNUCLEAR SECURITY IN THE COUNTER-TERRORISM STRUGGLE: India and Pakistan asa New Region for Cooperation, , August 200236